Employment Standards Branch
FACTSHEET

यह तथ्य-पत्र सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह कानूनी दस्तावेज़ नहीं है। कानून की व्याख्या व लागू किये जाने के उद्देश्य के लिये कृपया *इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ एक्ट* एंड *रैग्युलेशन* का हवाला लें।

July 2016

शिकायत का समाधान

इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ ब्रांच कर्मचारियों व नियोक्ताओं को अपनी समस्याओं को बिना सरकारी हस्तक्षेप के सुलझाने के लिये प्रोत्साहित करती है। यदि दल स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, तो ब्रांच समाधान के लिये बीच बचाव की कोशिश करेगी या, यदि आवश्यक हो तो, निर्णय भी जारी करेगी।

अधिकारों व कर्त्तव्यों को समझना

ब्रिटिश कोलम्बिया में *इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ एक्ट* तथा अधिनियम अधिकांश कर्मचारियों के लिये कार्यस्थल के कमसेकम मानदंड स्थापित करते हैं। कुछ व्यवसायी [प्रोफ़ैशनल्ज़] पूरे या आंशिक रूप से नियम से मुक्त हैं। कुछ क्षेत्र तथा उद्योग नौकरी के विशेष अधिनियमों से आबद्ध हैं जो केवल उन्हीं पर लागू होते हैं।

रोज़गार के अधिनियमों की जानकारी, जिसमें कानून व विभिन्न विषयों पर तथ्य-पत्रों की गाइड सम्मिलित है, किसी इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ ब्रांच के कार्यालय या ब्रांच की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

कानून के अनुसार, शिकायत करने के लिये छह-महीने की समयावधि नियत की गई है। यह जानने के लिये कि क्या नियोक्ता कर्मचारी की धनराशि का देनदार है, ब्रांच छह-महीने तक पीछे जाने की सीमा भी नियत करती है।

स्वावलम्बन किट का प्रयोग

वेतन के भुगतान या अन्य मुद्दों पर मतभेद को सुलझाने के लिये कर्मचारी का पहला कदम स्वावलम्बन किट के प्रयोग से सीधे नियोक्ता को सम्पर्क करना है। किट कर्मचारी को समस्या को परिभाषित करने तथा इच्छित सुझाव को पहचानने में [निम्न के द्वारा] सहायता करती है:

- इस निर्णय के लिये कि क्या *इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ एक्ट* उसकी स्थिति पर लागू होता है या नहीं;
- यह जांचने के लिये कि क्या नियोक्ता कानून की अवहेलना कर रहा है;
- वह कितनी धनराशि का देनदार है; तथा
- नियोक्ता को एक लिखित अनुरोध करने के लिये कि वह धनराशि देदे या कानून के भीतर अपेक्षित बदलाव करे।

यदि नियोक्ता कर्मचारी के अनुरोध से सहमत है, धन का भुगतान सीधे कर्मचारी को किया जा सकता है। इस स्तर पर मुद्दा सुलझ गया है।

स्वावलम्बन किट अपेक्षित नहीं

विशेष परिस्थितियों में, कर्मचारी के लिये किट का प्रयोग करना अपेक्षित नहीं होगा। उदाहरणतया:

- नियोक्ता का व्यवसाय बंद हो चुका है;
- इस मुद्दे से संबन्धित व्यक्ति 19 वर्ष से कम आयु का है;

शेष अगले पृष्ठ पर...

- शिकायत कानून के अनुमोदित छुट्टी प्रावधान से सम्बन्धित है (गर्भावस्था छुट्टी, माता-पिता बनने की छुट्टी, प्रियजन की मृत्यु पर छुट्टी, सहानुभूति पूर्ण देखभाल के लिये छुट्टी, पारिवारिक उत्तरदायित्त्व के लिये छुट्टी, या जूरी का कर्त्तव्य);
- कर्मचारी खेतों में काम करने वाला है, वस्त्र या कपड़ा उद्योग में है, या घरेलू कार्यकर्त्ता है ;
- कर्मचारी को भाषा या समझ में बहुत अधिक कठिनाई है; या
- कर्मचारी ने नियोक्ता को मामला सुलझाने की कोशिश में पहले से ही पत्र भेज दिया है।

शिकायत दर्ज करना

यदि कोई कर्मचारी किट के प्रयोग से मतभेद सुझाने में असफल रहा है, यदि कोई नियोक्ता जवाब नहीं देता है, या यदि कर्मचारी के लिये किट का प्रयोग अपेक्षित नहीं है, तो कर्मचारी इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ ब्रांच में शिकायत कर सकता है।

इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ ब्रांच की शिकायतें लिखित होनी चाहियें, इन्हें फ़ैक्स से, डाक से, व्यक्तिगत रूप से दिया या ऑनलाइन पर भी जमा करवाया जा सकता है। शिकायतकर्त्ता को अपनी शिकायत से सम्बन्धित सभी प्रमाण उपलब्ध कराने चाहियें।

मतभेद समाधान

यद्यपि कुछ मुद्दे जाँच के द्वारा सुलझाये जाते हैं, लेकिन अधिकांश शिक्षा, मध्यस्थता, तथा / या न्याय निर्णय के द्वारा सुलझाये जाते है।

जाँच

यदि कोई मुद्दा जाँच के लिये दिया गया है, तो जाँच अधिकारी दोनो दलों की ओर से जानकारी व प्रमाण इकट्ठे करेगा। जवाब के लिये जाँचकर्त्ता दोनों दलों की स्थिति व प्रमाण दूसरे दल के सामने रखेगा। अधिकारी अनौपचारिक रूप से शिकायत का समाधान करने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि यह संभव न हुआ तो अधिकारी एक निर्णय लेगा और न्यायालय निर्णय जारी करेगा।

शिक्षा

इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ ब्रांच के कर्मचारी शिकायत का तथा प्रदान किये गये प्रमाण का पुनरीक्षण करेंगे। अधिक जानकारी पाने तथा कानून के प्रावधान को समझाने के लिये ब्रांच दोनों दलों से सम्पर्क करेगी। यदि इस स्तर पर नियोक्ता शिकायत को सुलझा लेता है तथा दी जाने वाली धनराशि दे देता है, तो आगे और कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी तथा फाइल बंद कर दी जायेगी।

यदि शिकायत का समाधान नहीं हुआ है, तो यह मध्यस्थता के लिये भेजी जायेगी। दोनो दलों से मतभेद को सुलझाने के लिये कुछ भी सहायक प्रमाण, जैसेकि भुगतान रजिस्टर की जानकारी, काम किये गये घंटों का हिसाब तथा भुगताया गया वेतन, और इसके संबन्ध में अनुशासन की कार्रवाई के प्रलेख लाने को कहा जायेगा।

मध्यस्थता

ब्रांच का एक अधिकारी मध्यस्थता का संचालन करेगा, जोकि नियोक्ता व कर्मचारी के बीच एक अनौपचारिक बैठक होगी । यह व्यक्तिगत रूप से या फ़ोन पर टेलीकान्फ़्रैंस के रूप में होगी। (देखें *इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ मीडिएशन* फ़ैक्टशीट)

यदि दोनो दल मतभेद को सुलझा लेते हैं, तो मध्यस्थता का संचालन करने वाला अधिकारी एक “सैटलमैंट एग्रीमैंट” [समझौता अनुबंध] तैयार करेगा जिस पर शिकायतकर्त्ता व नियोक्ता दोनों हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर हो जाने के बाद, यह अनुबंध दोनो दलों के लिये बाध्यकारी होगा। यदि

शेष अगले पृष्ठ पर...

इसका सम्मान न रखा गया, तो यह उच्चत्तम न्यायालय में भी दर्ज हो सकता है तथा न्यायालय के आदेशानुसार लागू किया जा सकता है।

यदि मध्यस्थता से भी मतभेद नहीं सुलझता, तो भी यह दोनो दलों को मुद्दे के स्पष्टीकरण में, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में, तथा स्वीकृत तथ्यों को पहचानने में तथा कौन से अन्य मुद्दे रह गये हैं यह समझने में सहायक हो सकता है।

न्याय निर्णय की सुनवाई

यदि मध्यस्थता के द्वारा शिकायत का समाधान नहीं हो पाता, ब्रांच एक अधिकारी द्वारा संचालित न्याय निर्णय की सुनवाई नियत करेगी। यदि सुनवाई नियत की गई है, तो दोनों दलों को आवश्यक साक्षियों के साथ इसमें उपस्थित होना अपेक्षित है। यह सुनवाई व्यक्तिगत रूप से या फ़ोन पर टेलीकान्फ्रैंस के रूप में होगी। (देखें *एजुडिक्टेशन हियरिंग* फ़ैक्टशीट)

न्यायालय का निर्णय – डिटरमिनेशंज़

यदि जाँच के अन्तर्गत मामला अनौपचारिक ढंग से, या मध्यस्थता / न्याय निर्णय की सुनवाई की प्रक्रिया के अंत तक सुलझाया नहीं गया, तो न्याय निर्णय का संचालक अधिकारी एक लिखित निर्णय जारी करेगा जिसे न्यायालय का निर्णय या डिटरमिनेशंज़ कहते हैं। यदि न्यायालय के निर्णय में यह पाया गया कि शिकायतकर्त्ता को धन मिलना चाहिये या कि नियोक्ता ने किसी तरह से कानून की अवहेलना की है, तो यह नियोक्ता को आदेश देगा धनराशि का भुगतान किया जाये, कानून की अवहेलना बंद की जाये तथा एक या अधिक अनिवार्य दंड भरे जायें।

यदि नियोक्ता आदेशित धनराशि नहीं देता, यह न्यायालय का निर्णय उच्चत्तम न्यायालय में दर्ज होगा तथा न्यायालय के निर्णय की तरह लागू किया जायेगा। इसमें मुद्दे को वसूली के लिये कोर्ट बैलिफ़ में भेजा जाना शामिल हो सकता है।

अपील

न्यायालय के निर्णय की इम्प्लॉयमैंट स्टैंडर्डज़ ट्रिब्युनल में अपील की जा सकती है। अपील की अधिक जानकारी ट्रिब्युनल वैबसाइट www.bcest.bc.ca पर उपलब्ध है।